आपकी खबरों का संसार...

अतुल्य संसार

संस्करणः जयपुर

हिन्दी समाचार पत्र...

RNI No.-RJHIN/2015/63826

web: www.atulyasansar.com

Digital Edition

www.liveworldnews.in

वर्षः 10 | अंकः 353 | जयपुर, शुक्रवार 03 जुलाई, 2026 | मूल्यः 2 रुपए | पृष्ठः 4

एसआई भर्ती... पेज 2

गहलोत बोले राजस्थान... पेज 3

राममंदिर चढ़ावा चोरी-2 आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी

अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गुरुवार दोपहर 3 बजे मंदिर पहुंची है। एसआईटी ने 11 दिन पहले 15 से 20 जून तक जांच की थी। उधर, अयोध्या पुलिस सुबह करीब 11 बजे राम मंदिर पहुंची। करीब दो घंटे तक जांच की। जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती है, उसे देखा। पुलिस ने जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला को 24 घंटे के लिए रिमांड पर लिया है। अविनाश के घर से राम मंदिर का संदूक, 20 लाख कैश, एक हजार से अधिक डॉलर और गहने मिले थे। वह चढ़ावे की गिनती करता था। इस बीच, सुबह 11.45 बजे अयोध्या में 500 से ज्यादा वकील स?क पर उतर आए। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर एफआईआर की मांग कर नारेबाजी की। सिविल लाइन चौकी जाकर उन तीनों समेत 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दी। प्रशासन ने चढ़ावा चोरी के आरोपियों के नए घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ऐसे घरों की पहचान कर ली है, जिनका नक्शा पास नहीं है या जिन्होंने नियम तोड़े। आरोपी लवकुश मिश्रा का शहादतगंज में बन रहा मकान और अनुकल्प मिश्रा का कौशल पुरी स्थित मकान पर बुलडोजर चल सकता है। दोनों चढ़ावे की गिनती करते थे। अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए ने लवकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को नोटिस थमा दिया है।

ट्रस्टी दिनेंद्र दास बोले- पूरी गलती गोपाल राव की

चढ़ावा चोरी मामले में अब ट्रस्ट के सदस्यों के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा- पूरी गलती गोपाल राव की है। वे राजनीति कर रहे हैं। वो सबको उलझा देते हैं। वो राम की परंपरा नहीं मानते। गोपाल राव राम मंदिर के निर्माण प्रभारी और ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य थे। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं।

आज ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से पूछताछ संभव

पुलिस ने अयोध्या जेल में 30 जून को आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ की थी, अब आगे जांच कर रही है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से रविवार को 3 घंटे पूछताछ हो चुकी है। अब उसे क्रॉस चेक करने के लिए अनिल मिश्रा से आज पूछताछ हो सकती है। आरोपियों लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा की नियुक्ति में उनके रोल की पड़ताल करेगी। चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया था। यूपी सरकार ने 13 जून को एसआईटी बनाई। 25 जून को एफआईआर हुई। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसी दिन मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया।

पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला को 24 घंटे के लिए कस्टडी में लिया

पुलिस ने जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला को 24 घंटे के लिए रिमांड पर लिया है। अविनाश के घर से 20 लाख कैश, एक हजार से अधिक डॉलर और गहने मिले थे। अविनाश की आज कोर्ट में पेशी थी। पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड मांगी थी। चढ़ावा चोरी में और कितने लोग शामिल हैं, ट्रस्टियों की क्या भूमिका थी जैसे सवालों का जवाब तलाश जाएगा।

चढ़ावा चोरी में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका की जांच कर रही एसआईटी

अयोध्या में एसआईटी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी अब मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव की भूमिका की जांच कर रही है। इससे पहले, एसआईटी ने 6 दिन जांच की थी। तब 8 आरोपियों के खिलाफ सबूत मिले थे। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई और जांच पुलिस ने शुरू कर दी। माना जा रहा है कि 6 जुलाई को अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट की बैठक होनी है। जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होना है। उससे पहले एसआईटी संदिग्धों की भूमिका तय करना चाहती है।

डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले- जो चोरी करेगा, उस पर कार्रवाई होगी

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- अखिलेश यादव जो कर रहे हैं, उससे सपा और रसातल में जा रही है। राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जिन लोगों ने परम तपस्वियों की तरह काम किया है, उनमें चंपत राय सहित तमाम लोग शामिल हैं। उन सबको इस घटना से पीड़ा है। लेकिन, इस विषय को जितना चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, उसका कोई औचित्य नहीं है। जो चोरी करेगा या गलत करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और होगी।

कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण बोले- मोदी-शाह ने पूरे सिस्टम को भ्रष्टा बनाया, राम मंदिर भी अछूता नहीं

राम मंदिर चढावा चोरी पर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, सिर्फ जांच से कुछ नहीं होगा। भारत के लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश में जो माहौल बनाया है, उसने पूरे लोकतांत्रिक सिस्टम को भ्रष्ट कर दिया है। पैसे के दम पर राजनीतिक पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, **MLA** और **MP** की खरीद-फरोख्त हो रही है और **MP** को दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। यह सब प्रधानमंत्री की सहमति से हो रहा है। जब आप पूरे सिस्टम को इतना भ्रष्ट बना देते हैं, तो राम मंदिर भी इससे अछूता नहीं रह सकता।

चंपत राय पर एफआईआर के लिए प्रदर्शन, ट्रस्टी अनिल मिश्रा से पूछताछ होगी

राम मंदिर विवाद पर केजरीवाल बोले- सच जानते थे, फिर भी चुप रहे मोदी

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाते हुए कहा कि- श्री राम मंदिर में इतने बड़े-बड़े घोटाले हो गए मोदी जी, आपको पता कैसे नहीं चला? सच तो ये है कि आपको सब कुछ पता था, लेकिन आप धृतराष्ट्र बने रहे। और जब देश के सामने सच आने लगा, तो आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए फर्जी एसआईटी बना दी।

अयोध्या में राम जन्मभूमि थाने तक वकीलों का मार्च

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राम जन्मभूमि थाने पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए अधिवक्ताओं के मार्च से पहले फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि हम अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है।

लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को नोटिस जारी

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम अयोध्या विकास प्राधिकरण ने उनके नाम पर बन रही बिल्डिंग को लेकर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण का कहना है कि जांच के दौरान निर्माण में नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई है।

महबूबा मुफ्ती खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी

ईरान ने विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया; बोली- मेरे लिए यह सम्मान की बात

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती 3 से 6 जुलाई के बीच तेहरान में होने वाले ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। उन्हें ईरान ने भारत की विशेष अतिथि के तौर पर आधिकारिक निमंत्रण भेजा है। महबूबा ने कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। जिंदगी में एक बार मिलने वाला ऐसा अवसर है। मैं खामेनेई को अंतिम श्रद्धांजलि देने तेहरान जाऊंगी। ईरान भाजपा, कांग्रेस और पीडीपी के नेताओं के अलावा जैन संत आचार्य लोकेश मुनि को भी न्योता भेज चुका है। भारत सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ईरान का अनुमान है कि अंतिम यात्रा में 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं, जो देश के इतिहास का सबसे बड़ा राजकीय अंतिम संस्कार होगा।

ट्रम्प बोले- ईरान पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि ईरान के परमाणु कायक्रम को खत्म करने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है।

इजराइल का ऐलान- लेबनान, सीरिया और गाजा से सेना नहीं हटेगी- इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि लेबनान, सीरिया और गाजा में सेना की तैनाती जारी रहेगी। जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ता, सैनिक वापस नहीं बुलाए जाएंगे।

टीएमसी के बागी गुट का दावा- पार्टी का सिंबल हमारा

चुनाव आयोग से जल्द फैसला लेने की मांग; 58 विधायक 29 दिन पहले अलग हुए थे

नई दिल्ली/कोलकाता। बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने चुनाव आयोग से हुई मुलाकात की जानकारी दी। ऋतब्रत पश्चिम बंगाल की उलुबेरिया पुरबा विधानसभा सीट से विधायक हैं। तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिला। विधायकों ने पार्टी में हुए संगठनात्मक बदलावों और नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मान्यता देने की मांग की। मुलाकात के बाद बागी गुट के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने कहा- हम ही असली TMC हैं, चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी। उम्मीद है वे जल्द फैसला लेंगे।

बद्रीनाथ-केदारनाथ के रास्ते में पत्थर गिरे, कई गाड़ियां फंसीं

मुंबई में भारी बारिश, समुद्र में 15 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं

भोपाल/जयपुर/लखनऊ/पटना। उत्तराखंड में मानसून के बाद भारी बारिश जारी है। गुरुवार को रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई जिलों में भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर लगातार पत्थर गिर रहे हैं। सुरक्षा के चलते केदारनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। महाराष्ट्र में भी तेज बारिश जारी है। मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में रेड अलर्ट है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 172एमएम बारिश हुई है। इधर, मध्य प्रदेश के इंदौर में बारिश में कार नाले में गिर गई। सीहोर में बारिश के तेज बहाव में बाइक भी बह गईं। बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गुरुवार दोपहर समुद्र में करीब 15 फीट ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी है। लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। तेज बारिश के बीच गुरुवार को साकीनाका इलाके में एक शख्स की खुले मैनहोल में गिरने से मौत हो गई। मानसून ने गुरुवार को 7 दिन की देरी से राजस्थान और 5 दिन की देरी से दिल्ली में एंट्री ली। दिल्ली में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। राजस्थान के जयपुर-दौसा समेत 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है।

अगले 2 दिन के मौसम का हाल

3 जुलाई: छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, केरलम, गोवा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है।

बिहार में 50-60किमी. की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी राजस्थान और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में तेज हवा चलेगी। राजस्थान में 30-40किमी. की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हीटवेव जारी रहेगी। **4 जुलाई:** आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा में भी तेज बारिश की चेतावनी है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होगी। सिक्किम, गोवा, तेलंगाना और कर्नाटक में समुद्र के करीबी इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के नागपुर-अमरावती रीजन में लगातार पांचवें दिन हीटवेव का अलर्ट है।

मोदी बोले- सुजुकी दो-तिहाई कारें भारत में बना रही

जापान की मदद से देश में खाद के 1000 कारखाने लगेंगे; पीएम ताकाइची को बहन कहा

नई दिल्ली। भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी को नई रफ्तार देने का फैसला किया है। भारत-जापान जॉइंट इकोनोमिक फोरम में प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी कंपनियों की दिक्कतें दूर करने के लिए जापान बिजनेस वीक शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत पीएमओ के सीनियर अधिकारी सीधे जापानी निवेशकों से बातचीत करेंगे। मोदी ने कहा कि आज दुनिया में बिकने वाली सुजुकी की दो-तिहाई कारें भारत में बन रही हैं और इन्हें 100 से ज्यादा देशों में निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जापान के सहयोग से देश में करीब 1000 खाद (फर्टिलाइजर) कारखाने लगाए जाएंगे। दोनों देशों ने अगले 10 साल में भारत में 10 ट्रिलियन येन के जापानी निवेश का लक्ष्य भी रखा है। पीएम मोदी और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने हरियाणा के खरखौदा में मारुति सुजुकी के चौथे वाहन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। अपने संबोधन की शुरुआत में पीएम मोदी ने साने ताकाइची को अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत और जापान की तकनीक, निवेश और उत्पादन क्षमता का मेल दोनों देशों के साथ-साथ पूरी दुनिया के लिए भी फायदेमंद साबित होगा।

सुजुकी की सालाना 30 में से 20 लाख कार भारत में बन रही

सुजुकी दुनिया में हर साल करीब 30 लाख (3 मिलियन) कारें बनाती है। इनमें से लगभग 20 लाख (2 मिलियन) कारें अकेले भारत में बनती हैं। यानी कंपनी की हर 3 में से 2 कारें (करीब 66%) भारत में तैयार होती हैं। भारत में ये कारें मारुति सुजुकी के हरियाणा और गुजरात के प्लांट में बनती हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में मारुति सुजुकी ने 20 लाख से अधिक कारों का उत्पादन किया और 3.32 लाख से ज्यादा कारें 100 से अधिक देशों में निर्यात कीं।

भारत के राजस्थान में 'मिनी जापान'

राजस्थान के अलवर जिले के नीमराना को भारत का मिनी जापान या जापानी टाउन कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहां बना देश का पहला जापानी इंडस्ट्रियल जोन है। इसे राजस्थान सरकार की एजेंसी **RIICO** और जापान की व्यापार संस्था **JETRO** ने मिलकर विकसित किया। इसका मकसद जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और कारोबार के लिए बेहतर माहौल देना था। करीब 1,160 एकड़ में फैले इस औद्योगिक क्षेत्र में आज 50 से ज्यादा जापानी कंपनियां काम कर रही हैं।

बेंगलुरु डे-केयर में 3 साल की बच्ची से बेरहमी

बाथरूम में बंदकर जेट से पानी डाला, वॉशिंग मशीन में बैठाया; शिकायत करने वाले को निकाला

बेंगलुरु। बेंगलुरु में आईटी कंपनी कैपजेमिनी के एचएएल कैंपस स्थित एक डे-केयर सेंटर में 2-3 साल के बच्चों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। 29 जून को घटना के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वीडियो में टॉयलेट में बंद बच्चा फर्श पर रोता दिखाई दे रहा है, जबकि एक महिला उसका वीडियो बना रही है। दूसरे वीडियो में बच्चे को टॉयलेट सीट पर बैठाकर उसके चेहरे पर जेट स्प्रे से पानी डाला जा रहा है। एक अन्य वीडियो में बच्चे को फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ड्रम में बैठाकर डराया जा रहा है। मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने पांच महिला केयरगिवर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी ने इस घटना की जानकारी मैनेजमेंट को दी थी लेकिन कार्रवाई करने के बजाय उसे नौकरी से निकाल दिया गया। डीसीपी सैदुलु अडावथ ने कहा कि डे-केयर में आने वाले बच्चे कैंपस में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के हैं, जिन्हें उनके माता-पिता ड्यूटी के दौरान यहां छोड़ते थे। वीडियो देखकर माता-पिता और अधिकारी दोनों हैरान रह गए। बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह बेहद गंभीर है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि डे-केयर सेंटर का संचालन सीधे कैपजेमिनी कर रही थी या कंपनी परिसर में किसी बाहरी एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी।

रक्तदान शिविर का पोस्टर विमोचन

जयपुर। अग्रवाल समाज सेवा समिति, जयपुर के तत्कालीन (पूर्व) अध्यक्ष एवं प्रख्यात समाजसेवी चंद्र प्रकाश जी भाड़े वाले (लोहे वाले) से 5 जुलाई रविवार को होने वाले रक्तदान शिविर का पोस्टर विमोचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही इस अवसर पर उन्हें दिनांक 05 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने हेतु सादर आमंत्रित किया गया। उन्होंने हमारे आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएँ एवं पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर अग्रवाल समाज सेवा समिति जगतपुरा के संरक्षक श्री महेश गुप्ता जी, पूर्व सचिव श्री पुनीत अग्रवाल जी, महासचिव उमेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्री निखिल अग्रवाल मौजूद रहे।

लाम्बा कलां के सरकारी स्कूल में निःशुल्क बैग-स्टेशनरी का वितरण

जयपुर। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाम्बा कलां में प्रवेश उत्सव के द्वितीय चरण के दौरान नामांकन वृद्धि को लेकर कक्षा 1 से 8 के समस्त छात्र छात्राओं को नि:शुल्क बैग एवं स्टेशनरी प्रधानाचार्य के पहल एवं प्रेरणा से समस्त स्टाफ द्वारा वितरित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत प्रशासक हेमराज तोगड़ा, विशिष्ट अतिथि समाज सेवी जितेंद्र गुर्जर (लाला), एसडीएमसी सदस्य नौरतमल, अभय कुमार जैन के साथ विभिन्न ग्रामवासी एवं अभिभावक उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य सी पी विजयवर्गीय ने बताया कि बच्चो को राज्य सरकार द्वारा दूध, यूनिफॉर्म,म ध्यांतर भोजन, किताबें आदि नि:शुल्क दी जाती है और पहल करते हुए स्कूल बैग, तीन कॉपियां, पेंसिल, सॉफ्नर, इरेज़र समस्त स्टाफ द्वारा कक्षा 1 से 8 के 65 बच्चो को वितरित किया गया ओर ग्रामवासियों से सरकारी विद्यालय में ज्यादा से ज्यादा प्रवेश दिलवाने हेतु प्रेरित उद्बोधन दिया गया। प्रशासक हेमराज तोगड़ा एवं लाला गुर्जर द्वारा प्रधानाचार्य की अच्छी पहल पर समस्त स्टाफ साथियों की भुरी भूरि प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया ओर निरंतर बच्चो को अच्छी शिक्षा देते हुए उनके भविष्य निर्माण की कामना की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ व्याख्याता रिंकू, कुमावत, शैलेन्द्र पुरोहित, शंकर लाल यादव, अक्षय जैन, गोपाल पारीक, प्रतीक अकोदिया, बिरजू ग्वाला ने अपने विचार व्यक्त किए और गोपाल पारीक द्वारा देश भक्ति गीत संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बड़े चलो सुनाया गया। मंच संचालन शुभम जोनवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर अन्य स्टाफ साथी ओम प्रकाश सैनी, रामदयाल बैरवा, दिव्या, ममता,संजीव, संदीप आदि उपस्थित रहे। नि:शुल्क बैग एवं स्टेशनरी पाकर सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों के चेहरे खिले हुए नजर आए।

पासपोर्ट पर भ्रम दूर करे सरकार, नागरिकता के प्रमाण पर स्पष्ट नीति बने: राजेन्द्र सेन

जयपुर। ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल सदस्य एवं पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर, ऑल इंडिया कांग्रेस ओबीसी विभाग राजेन्द्र सेन ने नागरिकता के प्रमाण को लेकर उत्पन्न भ्रम पर केंद्र सरकार से तत्काल स्पष्टता की मांग की है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय के हालिया बयान में पासपोर्ट को केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रा का दस्तावेज बताया गया है, जबकि चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में इसे सहायक दस्तावेज के रूप में स्वीकार कर रहा है। इससे आम नागरिकों के मन में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। राजेन्द्र सेन ने कहा कि वर्षों से देश के नागरिक यह मानते रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा सभी आवश्यक जांच और पुलिस सत्यापन के बाद जारी किया गया पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है। यदि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं है, तो केंद्र सरकार स्पष्ट रूप से बताए कि भारतीय नागरिकता सिद्ध करने वाला वैधानिक दस्तावेज कौन-सा है। उन्होंने कहा कि देश में आज भी लाखों लोगों के पास जन्म प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है तथा अनेक नागरिकों के विभिन्न दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरणों में भिन्नता पाई जाती है।

ऐसी स्थिति में यदि नागरिकता सिद्ध करने की नौबत आती है, तो आम नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। राजेन्द्र सेन ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से मांग की कि नागरिकता के प्रमाण संबंधी स्पष्ट, एकरूप और पारदर्शी दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि देश के नागरिकों के मन में किसी प्रकार का भ्रम या भय न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों की विश्वसनीयता और नागरिकों का उन पर विश्वास बनाए रखना लोकतंत्र और सुशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

समाज सेवा ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य: डॉ. दौलत राम माल्या

जयपुर। प्रख्यात वास्तुकार, समाजसेवी एवं समर्पण संस्था के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. दौलतराम माल्या ने कहा कि जीवन की वास्तविक सफलता व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने से मिलती है। उन्होंने कहा कि समाज सेवा के लिए धन से अधिक सेवा-भाव और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। बॉक्स एफएम पर प्रसारित विशेष साक्षात्कार में डॉ. माल्या ने अपने जीवन के संघर्ष, सामाजिक कार्यों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि उनका जन्म जयपुर के निकट एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ। संत निरंकारी मिशन से जुड़े पारिवारिक वातावरण से उन्हें बचपन से ही सेवा और मानवता के संस्कार मिले। आर्थिक कठिनाइयों के बीच पढ़ाई के दौरान उन्होंने ईंट-भट्टों पर भी काम किया, लेकिन परिस्थितियों के आगे कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बताया कि संघर्षों ने ही उन्हें समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी। इसी उद्देश्य से उन्होंने समर्पण संस्था की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्तदान, वस्त्र बैंक, राशन सहायता, चिकित्सा सहयोग और आपदा राहत जैसे अनेक क्षेत्रों में लगातार कार्य कर रही है।

डॉ. माल्या ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना चाहिए। उन्होंने जापानी अवधारणा इकिगाई का उल्लेख करते हुए कहा कि जब व्यक्ति अपने उद्देश्य के साथ कार्य करता है, तभी जीवन सार्थक बनता है। वास्तुकला पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि केवल भवन बनाना पर्याप्त नहीं है। उसमें अपनापन, प्रेम और मानवीय संवेदनाएं हों, तभी वह मकान से घर बनता है। उन्होंने कहा कि वास्तुशास्त्र का अपना महत्व है, लेकिन सकारात्मक सोच और जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करने की क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार में उन्होंने समर्पण संस्था की महत्वाकांक्षी परियोजना दादा-पोता निवास की भी जानकारी दी। इस परियोजना के तहत अनाथ बच्चों और अकेले रह रहे बुजुर्गों को एक ही परिसर में रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

एसआई भर्ती-2021 री-एग्जाम में याचिकाकर्ताओं को राहत: हाईकोर्ट ने कहा-मूल एग्जाम में फॉर्म भरने वालों को भी शामिल करें

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती-2021 की पुन: परीक्षा को लेकर याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है। जस्टिस गणेशराम मीणा की अदालत ने आरपीएससी को गुरुवार को निर्देश दिए कि वे सभी याचिकाकर्ताओं को फॉर्म एडिट का मौका देकर प्रोविजनली परीक्षा में शामिल करें। कोर्ट ने यह आदेश हवा सिंह व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। कोर्ट ने कहा- प्रशासनिक असुविधा किसी पात्र अभ्यर्थी को अवसर से वंचित करने का वैध आधार नहीं हो सकती हैं। दरअसल, आयोग ने 8 मई को प्रेस नोट जारी करके मूल परीक्षा में दोनों पेपर देने वाले अभ्यर्थियों को ही 16 से 30 मई तक आवेदन एडिट करने का मौका दिया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था- उन्होंने मूल भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन तो किया था, लेकिन विभिन्न वास्तविक एवं अपरिहार्य कारणों से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। जिसके कारण उन्हें पुन: भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया हैं। आरपीएससी ने कहा था- 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने मूल परीक्षा में केवल एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, लेकिन परीक्षा नहीं दी थी। इनमें से कई अभ्यर्थी अन्यत्र नौकरी लग चुके होंगे। कई अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी छोड़ चुके होंगे। अगर हम सभी को अलाऊ

करते हैं तो हमें 4 लाख फॉर्म की अतिरिक्त छंटनी करनी होगी, जो बहुत मुश्किल काम है।

भर्ती प्रक्रिया में शामिल शब्द की संकीर्ण व्याख्या की गई

याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए वकील रघुनंदन शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 को रद्द करते हुए साल 2021 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। वहीं इस आदेश की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 मई 2026 को की थी। इसलिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थी का अर्थ केवल लिखित परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं माना जा सकता हैं। सभी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा तभी हो सकती है, जब पुन परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को शामिल होने का समान अवसर दिया जाए।

कोर्ट ने अपने आदेश में माना कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल शब्द की संकीर्ण व्याख्या कर केवल परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों तक सीमित करना प्रथम दृष्टया उचित नहीं है। ऐसे में कोर्ट ने सितंबर में होने वाली परीक्षा में याचिकाकर्ताओं को शामिल करने के निर्देश दिए।

भर्ती में 7.95 लाख अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन

दरअसल, एसआई भर्ती-2021 में करीब 7.95 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। हालांकि 13 से 15 सितंबर 2021 में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में 3 लाख 83 हजार 097 अभ्यर्थी ही बैठे थे। ऐसे में आयोग अब पुन- परीक्षा में भी इन्हीं अभ्यर्थियों को ही शामिल कर रहा है।

कोर्ट ने रद्द कर दी थी भर्ती

राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2025 को स्कू भर्ती-2021 को रद्द करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने 4 अप्रैल 2026 को फैसला सुनाते हुए इस आदेश को बरकरार रखा था। खंडपीठ के इस फैसले को ट्रेनी एसआई (चयनित अभ्यर्थियों) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन 4 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने चयनित अभ्यर्थियों की स्पेशल लीव पिटीशन को खारिज कर दिया।

राजस्थान में 7 दिन की देरी से मानसून की एंट्री

16 जिलों को किया कवर, इस बार कम बारिश होने की आशंका

जयपुर। राजस्थान में गुरुवार को मानसून की एंट्री हो गई। प्रदेश में 7 दिन की देरी से मानसून पहुंचा है। मानसून ने 16 जिलों झालावाड़, कोटा, बूंदी, भरतपुर, बारां, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, चित्तौडगढ़, बांसवाडा, प्रतापगढ, भीलवाड़ा और अलवर को कवर कर लिया। मौसम विभाग ने राज्य में अगले तीन दिन बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं, राज्य के दूसरे हिस्सों में भी मानसून के जल्द ही पहुंचने की उम्मीद है। इस सीजन मानसून औसत से कम बरसने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने 4 महीने (1 जून से 30 सितंबर) का मानसून सीजन माना है। राजस्थान में मानसून की एंट्री का समय 25 जून निर्धारित है, जबकि विदाई का समय 17 सितंबर है। पीक समय जुलाई और अगस्त माना जाता है। बता दें कि इस बार देश में मानसून केरलम में निर्धारित समय से 4 दिन की देरी से एंटर हुआ था।

औसत से कम बारिश का पूर्वानुमान

राजस्थान में इस बार मानसून सीजन कमजोर रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने राज्य में इस बार औसत से 10 फीसदी या उससे भी कम बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। राज्य में एक मानसून सीजन (1 जून से 30 सितंबर तक) में औसत 435.6एमएम बरसात होती है।

17 साल में 11 बार देरी से आया मानसून

राजस्थान में साल 2019 तक मानसून के प्रवेश का सामान्य समय 15 जून निर्धारित था। साल 2010 से 2019 तक केवल एक बार (साल 2013 में) ही निर्धारित समय पर मानसून राजस्थान में आया। जबकि 9 बार देरी से प्रवेश किया। इसके बाद केंद्रीय मौसम विज्ञान ने डेटा का रिव्यू किया और उसके आधार पर साल 2020 से मानसून के प्रवेश की सामान्य तारीख को 25 जून घोषित किया। साल 2020 से 2026 तक केवल दो बार (साल 2022 और 2026) मानसून देरी से राजस्थान में आया, जबकि 5 बार समय पर या उससे पहले मानसून की एंट्री हुई।

जानें साल 2025 में कैसा रहा मानसून

राजस्थान में साल 2025 में मानसून सीजन (1 जून से 30 सितंबर तक) में कुल 715.9एमएम बरसात हुई, जो औसत बारिश (435.6एमएम) से 64 फीसदी ज्यादा रही। राज्य में ये दूसरा मौका था, जब मानसून सीजन में इतनी बरसात हुई। पिछले साल हुई इस बारिश ने 108 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। राजस्थान के इतिहास में अब तक मानसून की सबसे ज्यादा बरसात साल 1917 में 844.2एमएम दर्ज हुई है। पिछले साल राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई थी। बूंदी, दौसा, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, बारां अतिवृष्टि से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे थे। बूंदी के नैनवां में पिछले सीजन में एक दिन में सर्वाधिक पानी बरसा था। यहां 23 अगस्त 2025 को 24 घंटे के दौरान 502एमएम बारिश दर्ज हुई थी। जबकि 20 अन्य ऐसे शहर या कस्बे रहे, जहां एक दिन में 200एमएम से लेकर 310 एमएम तक बरसात हुई थी। जिलेवार स्थिति देखें तो पिछले साल श्रीगंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़, टोंक, सवाई माधोपुर और दौसा में औसत से दोगुनी बारिश हुई थी।

डकैत जगन गुर्जर हत्याकांड की हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी

कहा- जेल से गिरोह ऑपरेट हो रहे; मुख्यमंत्री तक को धमकी मिल चुकी है

जयपुर। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में हुए डकैत जगन गुर्जर हत्याकांड की रिपोर्ट हाईकोर्ट ने तलब की है। कोर्ट ने जेल में घटना से जुड़े कैमरों में क्या रिकॉर्ड हुआ, क्या नहीं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की गई है। इन तमाम बिंदुओं पर कोर्ट ने सरकार और जेल प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश जेल में व्यवस्थाओं के सुधार से जुड़े स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में सुनवाई करते हुए दिए। कोर्ट मामले में टिप्पणी करते हुए कहा-प्रदेश की जेलों में यह क्या हो रहा है। हाई सिक्योरिटी जेल में कैमरे में रिकोर्डिंग नहीं हो रही है। कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है।प्रदेश की जेलों में आसानी से मोबाइल पहुंच रहे हैं। यहां तक कि जेल से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी धमकी मिल चुकी है। इसके बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। रिपोर्ट के बाद भी व्यवस्थाएं नहीं सुधरी मामले में न्यायमित्र वकील प्रतीक कासलीवाल ने कहा- कोर्ट लगातार जेलों में व्यवस्था सुधार के लिए निर्देश दे रहा है। हमारी पिछली रिपोर्ट में भी बताया था कि हाई सिक्योरिटी जेल में सीसीटीवी कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कई कैमरों के कनेक्शन तक नहीं है, लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट पर ध्यान तक नहीं दिया। जेल से गिरोह ऑपरेट हो रहे हैं कोर्ट ने कहा- हम लगातार मीडिया में देखते हैं कि जेल से गिरोह ऑपरेट हो रहे हैं। लोगों को वसूली के लिए जेल से धमकियां दी जाती है। यहां तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी जेल से धमकी मिल चुकी है। ऐसे में इस तरह की घटना सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की।

देशनोक सेवा शिविर राम भरोसे: जनसेवा के नाम पर सिर्फ 'खानापूर्ति'

देशनोक। राज्य सरकार ने जिस मंशा के साथ आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और एक ही छत के नीचे उनके सारे काम हो जाएं, इसी उद्देश्य के साथ सेवा शिविर योजना की शुरुआत की । लेकिन देशनोक नगरपालिका परिसर में चल रहा सेवा शिविर इस मंशा के ठीक विपरीत जनता के लिए आफत का सबब बन चुका है। शिविर में समाधान तो दूर, आमजन स्थानीय प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण चक्कर घिन्नी बनने को मजबूर हैं। हालात यह हैं कि शिविर में दैनिक और रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़े काम भी ठप पड़े हैं, जिससे स्थानीय जनमानस में अब एक ही चर्चा जोरों पर है- यह सेवा शिविर है या सिर्फ कागजी खानापूर्ति?

अधिकारी गायब, सूनी पड़ी हैं टेबलें

सरकार ने बड़ी उम्मीदों के साथ इस शिविर का आगाज़ किया था, लेकिन यहाँ का धरातल कुछ और ही कहानी बयाँ कर रहा है। शिविर में कई महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी और कर्मचारी सिरे से गायब हैं। विभागों के नाम की तख्तियाँ और टेबलें तो सजी हैं, लेकिन उन पर बैठने वाली कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं। शिविर प्रभारी तक की सीट खाली होने से प्रशासनिक गंभीरता का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है।

सुबह 10:40 तक सिर्फ दो राशन डिपो होल्डर मिले!

पूर्व पार्षद लक्ष्मण दान ने प्रशासन की पोल खोलते हुए बताया कि वे सुबह 10ः00 बजे शिविर स्थल पर पहुंचे थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि सुबह 10ः40 बजे तक शिविर में मात्र दो राशन डिपो होल्डर्स के अलावा कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था। राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिजली और पानी जैसी बुनियादी और रोजमर्रा की शिकायतों से जुड़ी फाइलें यहाँ सिर्फ धूल फांक रही हैं। पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लोगों ने कहा कि जब पूरा सेवा शिविर पालिका के मुख्य सभागार (हॉल) के अंदर सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, तो फिर बाहर पार्क में अलग से टेंट लगाने का क्या औचित्य है? **न पानी, न कुर्सी:** इस भीषण गर्मी में पार्क में लगाए गए टेंट के नीचे न तो आमजन के बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं और न ही पीने के ठंडे पानी की कोई व्यवस्था है। **प्रचार-प्रसार शून्य:** शिविर का प्रचार-प्रसार इतना कमजोर है कि आम जनता को इसकी सही जानकारी तक नहीं है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के जन्मदिवस पर गौसेवा की गई, फलों का हुआ वितरण और राहगीरों को पिलाई शरबत

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के जन्मदिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं की ओर से विविध सेवा कार्य किए गए। भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग कीओर से जहां अस्पताल परिसर में फल वितरित किए गए, वहीं भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से शीतल शरबत वितरित किया गया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ ने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यालय पर ओबीसी मोर्चा की ओर से भाजपा महामंत्री संगठन अजेय कुमार, भाजपा राष्ट्रीय मंत्री व राज्यसभा सांसद डॉ. अलका गुर्जर एवं ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉ महेंद्र कुमावत के मुख्य आतिथ्य में शीतल शरबत वितरण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने राहगीरों को शरबत पिलाकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा मीडिया विभाग द्वारा एसएमएस अस्पताल परिसर में फल वितरित किए गए। वशिष्ठ ने कहा कि सेवा ही संगठन का मूल मंत्र है। इसी भावना के साथ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के जन्मदिवस को सादगी एवं सेवा कार्यों के माध्यम से मनाया गया। राठौड़ का सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, संगठन के प्रति समर्पण एवं जनसेवा की भावना सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उ

नके जन्मदिवस पर जरूरतमंदों की सेवा करते हुए फल वितरित किए गए। इस अवसर पर भाजपा मीडिया विभाग की पूरी टीम एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं सफल नेतृत्व की कामना करते हुए सेवा कार्यों के माध्यम से समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

भाजपा प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक ने बताया कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर राजस्थान गौ सेवा संघ दुर्गापुरा जयपुर द्वारा संचालित गोशाला में गायों को हरा चारा, लड्डू व रोटी खिलाकर सेवा की। इस दौरान भाजपा उपाध्यक्ष सरिता गैना, प्रदेश मंत्री डॉ अपूर्वा सिंह, भाजपा नेता प्रो विक्रम सिंह गुर्जर, शैलेश शर्मा, श्रीकिशन शर्मा व सुनील पाराशर उपस्थित रहे। भाजपा कार्यालय पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, प्रदेश मंत्री अजीत मांडण, सीताराम पोसवाल, नारायण मीणा, डॉ.अपूर्वा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता स्टेफी चौहान, कार्यालय मंत्री मुकेश पारीक , मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामेश्वर गुर्जर, भंवरलाल जांगिड, संजय जायसवाल उपाध्यक्ष चेतन कुमावत, शिव देशवाल, मोर्चा पदाधिकारी बद्री सामरिया, भवानी सिंह चारण, विजेंद्र चौधरी सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

गहलोत बोले- राजस्थान में सरकारी भुगतान तंत्र ठप

ऐसा वित्तीय कुप्रबंधन कभी नहीं देखा, न पेंशन मिल रही न इलाज, सीएम तुरंत दखल दें

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी भुगतान तंत्र के पूरी तरह ठप होने का दावा करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा को लैटर लिखा है। गहलोत ने लैटर में गंभीर वित्तीय संकट का हवाला देते हुए सरकारी कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों और वेंडर्स का भुगतान नहीं होने पर सवाल उठाए। गहलोत ने लैटर में लिखा- राजस्थान में सरकारी भुगतान तंत्र जिस तरह ठप पड़ चुका है, उसे लेकर मैं गहरी चिंता के साथ यह लिख रहा हूं। यह किसी एक विभाग या किसी एक योजना की समस्या नहीं है। कर्मचारी, पेंशनभोगी, दुर्घटना पीड़ित परिवार, अस्पताल, दवा विक्रेता और छोटे ठेकेदार, लगभग हर वर्ग आज अपने वाजिब भुगतान के लिए भटक रहा है। प्रदेश के इतिहास में वित्तीय कुप्रबंधन का ऐसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा गया। गहलोत ने कहा- मुख्यमंत्री को समय रहते इसमें हस्तक्षेप कर लोगों को राहत दिलानी चाहिए।

आरजीएचएस योजना में अस्पतालों-मेडिकल स्टोरों का भुगतान अटका

गहलोत ने लिखा- आरजीएचएस योजना के तहत निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और दवा विक्रेताओं का करोड़ों रुपए का भुगतान महीनों से अटका है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि राज्य मानवाधिकार आयोग को इसे मानवाधिकार उल्लंघन मानते हुए स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। कई अस्पतालों ने योजना से जुड़ी सेवाएं सीमित करने या एमओयू समाप्त करने तक की चेतावनी दे डाली। नतीजा यह है कि कैशलेस इलाज का दावा करने वाली योजना में भी कर्मचारियों और पेंशनरों को पहले अपनी जेब से पैसे जमा करवाने पड़ रहे हैं। इस भरोसे पर कि सरकार से भुगतान आने पर बाद में वापसी होगी।

ऐसे मामलों में राज्य सरकार को लिखित गारंटी देकर अस्पतालों को पुनर्भुगतान के लिए पाबंद करना चाहिए।

एक्सीडेंट में मौत पर पांच लाख की सहायता भी नहीं मिल रही

गहलोत ने लिखा- मुख्यमंत्री चिरंजीवी, आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत भी रुपए नहीं मिल रहे हैं। इसके तहत दुर्घटना में मौत होने पर पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपए की सहायता राशि मिलनी होती है। यह जानकारी मिल रही है कि सैकड़ों मामलों में दावे स्वीकृत होने के बावजूद पीड़ित परिवारों को भुगतान नहीं मिल पाया है। जिस परिवार ने अपना कमाने वाला सदस्य खोया हो, उसे स्वीकृति के बाद भी महीनों राशि के लिए इंतजार करना पड़े, यह राज्य सरकार की असंवेदनहीनता को दिखाता है।

रिटायरमेंट के बाद कई महीनों तक कर्मचारियों को नहीं मिल रहे रुपए

गहलोत ने लिखा- राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों की हालत भी उतनी ही चिंताजनक है। जीपीएफ, ग्रुप बीमा, ग्रेच्युटी और अर्जित अवकाश (पीएल) जैसी रकम, जो कर्मचारी का हक है। रिटायरमेंट के बाद कई महीनों तक जारी नहीं हो रहा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी प्रदेश के कई जिलों में कई महीनों से लंबित चल रही है। इससे बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशनभोगी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

ट्रेजरी से पास हो चुके बिलों का भुगतान नहीं हो रहा

गहलोत ने लिखा- ट्रेजरी से पास हो चुके बिलों के भुगतान पर भी कई महीनों से संकट बना हुआ है। इसका सीधा असर सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं पर पड़ रहा है। हालत यह हो गई है कि छोटे-छोटे ठेकेदारों को अपने वाजिब भुगतान के लिए अखबारों में विज्ञापन देकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है। हजारों श्रमिकों और छोटे उद्यमियों की आजीविका इसी भुगतान संकट के कारण खतरे में है।

भुगतान संकट प्रशासनिक लापरवाही नहीं

गहलोत ने लिखा- भुगतान का यह संकट केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका और सम्मान से जुड़ा प्रश्न है। जिस राज्य को अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और सेवा प्रदाताओं के भरोसे पर खड़ा होना चाहिए, वहां आज यह भरोसा ही डगमगा रहा है। आम आदमी, सरकारी कार्मिक, पेंशनभोगी, ठेकेदार समेत समाज का हर वर्ग आज परेशान है। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए समय रहते निर्णय लेना जरूरी है, ताकि प्रदेश के लाखों परिवारों को इस अनावश्यक संकट से राहत मिल सके।

डमी कैंडिडेट बैठाकर बनी वनरक्षक, एसओजी ने किया अरेस्ट

रीट एग्जाम में धांधली करते गई थी पकड़ी, धोखे से पुलिस सत्यापन करा जॉइनिंग भी कर ली

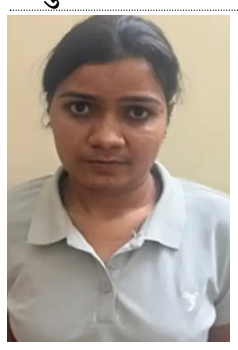

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने डमी कैंडिडेट बैठाकर वनरक्षक बनी युवती को अरेस्ट किया है। रीट भर्ती में भी डमी कैंडिडेट से एग्जाम दिलवाने से पहले जयपुर की सिंधीकैम्प थाना पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। पुलिस केस दर्ज होने के बाद भी धोखे से पुलिस सत्यापन बनवाकर आरोपी युवती ने वनरक्षक जॉब की जॉइनिंग की थी। एसओजी की ओर से फिलहाल आरोपी युवती से पूछताछ की जा रही है। एडीजी (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया- वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 चीटिंग मामले में आरोपी प्रमिला (29) निवासी सरनाऊ सांचौर जालोर को अरेस्ट किया गया है। वह वनरक्षक वनपाल नाका जीरावल रेवदर सिरोही है।

राजसमंद के कांकरोली में आया था एग्जाम सेंटर

वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 की एग्जाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से साल-2022 में आयोजित हुई थी। 13 नवम्बर-2022 को प्रमिला का एग्जाम सेंटर राजसमंद के कांकरोली में आया था। मेन कैंडिडेट प्रमिला की ओर से अपनी जगह पर वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 में डमी कैंडिडेट को बैठाकर परीक्षा दिलवाई थी। डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा पास कर वनरक्षक भर्ती में उसका चयन हुआ था। एसओजी में साल-2025 में दर्ज प्रकरण में जांच के दौरान चीटिंग का पता चलने पर आरोपी प्रमिला को अरेस्ट किया गया है।

रीट भर्ती में पकड़ी गई थी

एसओजी की जांच में सामने आया कि प्रमिला की ओर से रीट भर्ती परीक्षा-2021 में भी अपने जगह डमी कैंडिडेट की फोटो लगाकर एग्जाम दिलवाने वाली थी। एग्जाम देने से पहले ही सिंधीकैंप थाना पुलिस ने दोनों (मेन व डमी कैंडिडेट) को पकड़ लिया था।

नगर-निगम का जमादार 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप

एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा, पट्टा दिलाने के लिए मांगे थे 2 लाख रुपए

जयपुर। भष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को 50 हजार रुपए की घूस लेते एक जमादार को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने जयपुर नगर निगम में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पट्टा संबंधी मामले में जमादार की ओर से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी की टीम फिलहाल आरोपी जमादार से पूछताछ कर रही है।

पट्टा बनवाने के लिए मांगी थी घूस

डीजी (एसीबी) गोविन्द गुप्ता ने बताया- जयपुर नगर निगम में एसीबी टीम ने गुरुवार दोपहर कार्रवाई की है। टीम ने आरोपी रामसिंह यादव (28) पुत्र मूलचन्द यादव निवासी श्रीमाधोपुर सीकर को अरेस्ट किया है। आरोपी रामसिंह यादव हवामहल-आमेर जोन नगर निगम जयपुर में पट्टा/लीज ब्रांच में जमादार के पद पर है। मामले में पीड़ित ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई कि जयपुर नगर निगम के हवामहल-आमेर जोन में उसके पिता के नाम पट्टा संबंधी मामला अटका हुआ है।

काम के एवज में मांगे थे 2 लाख रुपए

पिछले काफी समय से पट्टा संबंधी काम करवाने के लिए वह चक्कर लगा रहा है। नगर निगम में तैनात जमादार रामसिंह की ओर से काम करने के एवज में 2 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। एसीबी की ओर से शिकायत का सत्यापन करवाया गया। रिश्वत डिमांड का पता चलने पर एसीबी की ओर से ट्रेप का चक्रव्यू रचा गया। एसीबी ने गुरुवार दोपहर परिवादी को रिश्वत की रकम के 50 हजार रुपए लेकर भेजा। जमादार की ओर से घूस के 50 हजार रुपए लेते ही एसीबी टीम ने उसे रंगे हाथों दबोचा लिया।

वीबी जी राम जी योजना - राज्य स्तरीय जन सम्मेलन सह शुभारंभः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन से गांवों में बहेगी विकास की गंगा

वीबी जी राम जी के लिए प्रदेश में 12 हजार 636 करोड़ का प्रावधान- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

ब्यावर/जयपुर। केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के तिरूपति से विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) गारंटी योजना के राष्ट्रीय शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्यावर जिले के मसूदा कृषि उपज मण्डी से इस कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने वीबी जी राम जी योजना के राज्य स्तरीय जन सम्मेलन सह शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों की समृद्धि और विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन में वीबी जी राम जी योजना लाई गई है। प्रधानमंत्री का स्पष्ट विश्वास है कि गांवों को विकसित बनाकर ही भारत को विकसित बनाया जा सकता है। किसान की समृद्धि, श्रमिक के सम्मान और गांव की आत्मनिर्भरता से भारत विश्व की अग्रणी शक्ति बनेगा। यह योजना रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ जल संरक्षण, आधारभूत संरचना और ग्राम विकास का समग्र राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने कहा कि मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देने के लिए लाया गया था, लेकिन यह अपने मकसद में पूर्ण सफल नहीं हो पाया। मनरेगा के तहत अधिकांश काम में अस्थायी सडकों, आधी-अधूरी जल संरचनाओं या बिना योजना के मिट्टी खुदाई जैसे कार्य होते थे, जिनका लंबी अवधि में कोई लाभ नहीं होता था। उन्होंने कहा कि जांच-पडताल की सुदृढ व्यवस्था नहीं होने से नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, फर्जी लाभार्थी, बढ़ा-चढ़ाकर या मनगढंत हाजिरी रजिस्टर और श्रमिकों को आंशिक भुगतान या पूरी मजदूरी न देने जैसी गडबडियां होती थी। साथ ही, सोशल ऑडिट केवल औपचारिकता के लिए होता था या होता ही नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत प्रशासनिक कार्यों के लिए केवल 6 प्रतिशत खर्च की अनुमति होने से योजना का बेहतर क्रियान्वयन संभव नहीं हो पाया। मनरेगा के काम खेती के सीजन में भी चलने के कारण किसानों को मजदूर नहीं मिल पाते थे और देरी से मजदूरी भुगतान पर मुआवजे के प्रावधान केवल कागजी बनकर रह गए थे। उन्होंने कहा कि अब वीबी जी राम जी योजना में सालाना रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिन से बडाकर 125 दिन किया गया है। फसल बुवाई और कटाई के समय श्रमिकों की कमी न हो इसके लिए राज्य सरकार 60 दिनों का कार्य विराम घोषित कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका और आपदाओं से निपटने संबंधी ठोस कार्य करवाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें जियो-टैगिंग, सैटेलाइट इमेज, मोबाइल ऐप और एआई जैसी तकनीकों का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हर छह महीने में कार्यों का डिजिटल तथ्यों के साथ सोशल ऑडिट अनिवार्य होगा। साथ ही, डिजिटल बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसमें निश्चित समय सीमा और जिला लोकपालों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर हफ्ते भुगतान करना अनिवार्य होगा। दो सप्ताह से अधिक की देरी पर स्वत: ही मुआवजा मिलेगा। वहीं, प्रशासनिक व्यय की सीमा को बडाकर 9 प्रतिशत किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशिक्षण और निगरानी क्षमता सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि इस योजना के कानून में एक टिकाऊ और जवाबदेह वित्तीय मॉडल का प्रावधान किया गया है। पहले श्रम बजट की कोई तय सीमा नहीं होती थी। अब उसकी जगह हर साल के लिए एक स्पष्ट और तय बजट निर्धारित किया गया है। लोगों की मांग के अनुसार काम देने की व्यवस्था पहले की तरह बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि कुल आवंटन में वृद्धि की गई है, जिससे राज्यों को हाल के मनरेगा औसत की तुलना में लगभग 17 हजार करोड रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी जी राम जी योजना को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। जबकि वास्तविकता ये है कि यह एक सहकारी संघवाद का मॉडल है। डबल इंजन सरकार द्वारा इस योजना के लिए वर्ष 2026-27 में 12 हजार 636 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है, जोकि राज्य में इस योजना का अब तक का सबसे अधिक बजट है। इससे गांवों में पानी और सडकों जैसे स्थायी काम होंगे, जिनकी वास्तव में आवश्यकता होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण भारत के भविष्य को नई दिशा देने वाली इस दूरदर्शी पहल का नेतृत्व किया है। यह योजना ग्रामीण रोजगार की मजबूत गारंटी और विकसित भारत की मजबूत आधारशिला बनेगी। उन्होंने कहा कि देवमाली गांव की देश-दुनिया में एक खास पहचान है। इस गांव को भारत सरकार ने बेस्ट टूरिस्ट विलेज का पुरस्कार भी दिया है। आज भी इस गांव में पक्का घर नहीं बनाया जाता तथा ताले नहीं लगाए जाते। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ढाई वर्षों में प्रदेश में पानी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। विभिन्न जल परियोजनाओं को साकार किया जा रहा है। 26 जिलों के किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। वर्ष 2027 तक प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे को भी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हरियालो राजस्थान के तहत पौधारोपण का अभियान चला रही है। आमजन अधिक से अधिक इस अभियान का हिस्सा बन पौधारोपण करें। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 2 करोड रुपये की लागत से देवमाली में दर्शनार्थियों के लिए आश्रय स्थल बनाने की घोषणा की। साथ ही, देवमाली में सरोवर के जीर्णोद्धार और सडकों के निर्माण से स्थानीय क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए भी आश्वस्त किया। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि वीबी जी राम जी योजना विकसित भारत की पक्की नींव है। इसमें होने वाले पक्के निर्माणों से गांवों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ढाई वर्षों में प्रदेश में महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं को गति देने के साथ ही किसान सम्मान निधि को बडाकर 9 हजार रुपये किया है। ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और प्रदेश तरक्की कर रहा है। वीबी जी राम जी योजना को मनरेगा से अधिक सुदृढ और प्रभावी बनाया गया है। आधारभूत ढांचों के निर्माण के महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। गांवों में अंतिम छोर तक इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने दी विभिन्न सौगातें

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वीबी जी राम जी योजना के तहत दो लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण किया। साथ ही, स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से क्रेडिट लिंकेज राशि 3.31 करोड रुपये के चेक एवं राजस्थान महिला निधि की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एसएचजी दीदियों को 1.16 करोड रुपये के ऋण चेक वितरित किए। उन्होंने समर्थ सखी ऋण योजना के तहत सीएलएफ कल्स्टर मैनेजर एवं बैंक मित्रों को स्कूटी प्रदान की। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नवीन आवासों की स्वीकृति तथा नवनिर्मित मकानों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। इससे पहले उन्होंने राजीविका स्वयं सहायता समूहों के हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल्स का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 424 करोड रुपये के विकास कार्यों का शिलान्डयास किया। इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाना, विधायक विरेन्द्र सिंह कानावत, शत्रुघन गौतम, शंकर सिंह रावत, रामस्वरूप लाम्बा, शासन सचिव ग्रामीण विकास कृष्ण कुणाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं बडी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

गिर शेरों पर मंडराता संकट: सीमित दायरा और मानव-वन्यजीव संघर्ष बनी सबसे बड़ी चुनौती

गिर में आठ एशियाई शेर शावकों की मौत चिंताजनक

सीमित आवास, बीमारियां और मानव-संघर्ष प्रमुख खतरे

शेरों के लिए दूसरा सुरक्षित ठिकाना बनाना आवश्यक

अहमदाबाद। गुजरात के गिर जंगलों से हाल ही में सामने आई आठ एशियाई शेर शावकों की मौत ने दुनिया भर के वन्यजीव प्रेमियों और संरक्षणवादियों को चिंता में डाल दिया है। इस घटना ने एक बार फिर दुनिया की एकमात्र जंगली एशियाई शेर आबादी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार के अनुसार, इन शावकों की मौत की मुख्य वजह अत्यधिक गर्मी, तनाव और कमजोर रोग इम्युनिटी रही है।

क्या है गिर पैराडॉक्स?

करीब एक सदी पहले एशियाई शेर विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए थे। इसके बाद शुरू हुए कड़े संरक्षण प्रयासों के चलते इनकी संख्या में अभूतपूर्व सुधार देखा गया। साल 2015 में जहां शेरों की संख्या 523 थी, वहीं जनवरी 2026 तक यह आंकड़ा बढ़कर 891 तक पहुँच गया है। इसे दुनिया के सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण अभियानों में गिना जाता है। लेकिन इस सफलता के साथ एक स्याह पहलू भी जुड़ा है, जिसे विशेषज्ञ गिर पैराडॉक्स कह रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि शेरों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, उनके लिए बीमारियां, सीमित प्राकृतिक आवास और इंसानों के साथ टकराव का खतरा भी उतना ही गहराता जा रहा है। यही वजह है कि पिछले तीन वर्षों

में रिकॉर्ड 322 शेरों की मौत दर्ज की जा चुकी है।

एक ही क्षेत्र में पूरी आबादी का होना सबसे बड़ा जोखिम

वन्यजीव विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी दे रहे हैं कि एशियाई शेरों की पूरी आबादी का सिर्फ एक ही भौगोलिक क्षेत्र (गिर) में केंद्रित होना बेहद खतरनाक है। यदि इस क्षेत्र में कोई गंभीर संक्रामक महामारी फैलती है या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है, तो शेरों की पूरी प्रजाति एक झटके में खत्म हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की दूसरी आबादी बसाने का ऐतिहासिक आदेश दिया था। हालांकि, यह योजना आज तक पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर सकी है। हालिया मौतों के बाद विशेषज्ञ एक बार फिर शेरों के लिए दूसरा सुरक्षित ठिकाना बनाने की मांग तेज करने लगे हैं।

बढ़ता मानव-शेर संघर्ष और अन्य हादसे

जंगल का दायरा सीमित होने और आबादी बढ़ने के कारण शेर अब अपने पारंपरिक आवास से बाहर निकलकर खेतों, गांवों और मानव बस्तियों का रुख कर रहे हैं। अमरेली, भावनगर और उसके आस-पास के इलाकों में मानव-शेर संघर्ष की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इसके अलावा, शेर खुले कुओं में गिरने, रेल व सड़क हादसों और खेतों के चारों ओर लगी बिजली की तारों के करंट का शिकार हो रहे हैं। गुजरात सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में शेर संरक्षण पर 37.35 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद, अगस्त 2023 से जुलाई 2025 के बीच 307 शेरों की मौत होना यह दर्शाता है कि केवल बजट बढ़ाना काफी नहीं है, बल्कि धरातल पर कड़े और नए उपायों की सख्त जरूरत है।

जेनेटिक बॉटलनेक की चुनौती

शावकों की हालिया मौतों के बाद बेबेसियोसिस नामक बीमारी का संदेह जताया जा रहा है। यह एक परजीवी रोग है जो संक्रमित किलनी के जरिए फैलता है और शेरों की लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला कर उन्हें गंभीर एनीमिया का शिकार बना देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। गिर में इससे पहले 2018, 2020 और 2021 में भी इसके मामले देखे जा चुके हैं। इसके अलावा, विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चिंता कैनाइन डिस्टेंपर वायरस को लेकर है, जिसने 2018 में गिर के 23 से अधिक शेरों की जान ले ली थी। एक ही क्षेत्र में सीमित रहने के कारण शेरों में आनुवंशिक विविधता भी खत्म हो रही है, जिसे वैज्ञानिक जेनेटिक बॉटलनेक कहते हैं। इसके कारण नई बीमारियों और पर्यावरण में होने वाले बदलावों के खिलाफ शेरों की प्राकृतिक ल?ने की क्षमता कमजोर हो रही है।

3 सेकंड में ढहाए गए सुभाष ब्रिज के तीन स्पैन, ध्वस्त हुआ 53 साल पुराना ब्रिज

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में 53 साल पुराना सुभाष ब्रिज अब अतीत बन चुका है। इस ब्रिज को पूरी तरह से तोड़ने के काम के तहत गुरुवार को नदी में बने ब्रिज के तीन स्पैन ढहा दिए गए। पूरे स्पैन को सुरक्षित तरीके से बहुत सावधानी के साथ नीचे उतारा गया। इस ब्रिज की जगह अब नया ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसके अगले साल (साल 2027) अप्रैल या मई महीने तक बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद सुभाष ब्रिज के ऊपरी हिस्से को तोड़कर इसका फिर से निर्माण करने का फैसला लिया गया था। ऊपरी हिस्सा तोड़े जाने के दौरान ब्रिज के स्पैन और पिलर को नुकसान पहुंचा। ऐसे में अधिकारियों ने इस ब्रिज को पूरी तरह से ध्वस्त कर इसकी जगह नए ब्रिज के निर्माण का फैसला किया। पहले इस ब्रिज के ऊपरी हिस्से का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए नौ महीने की समय-सीमा तय की गई थी। अब इस काम में 16 महीने लगने की संभावना जताई जा रही है। इस पुल को आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हुए बहुत ही सावधानीपूर्वक तोड़ा गया। ब्रिज के ध्वस्तीकरण की पूरी कार्यवाही कैमरे में कैद की गई। साबरमती नदी पर इस पुल का निर्माण 1973 में कराया गया था। इस पुल की लंबाई 453।7 मीटर और चौड़ाई 12।8 मीटर थी। इसकी जगह नए पुल का निर्माण अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करा रहा है। इस पर कुल 235 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि खर्च होने का अनुमान है। नए पुल का निर्माण आधुनिक तकनीक की मदद से किया जाना है।

किसान एमएसपी पर बेच सकेंगे जायद मूंग की फसल, गुजरात में 7 जुलाई से शुरू होगी खरीद

अहमदाबाद। गुजरात सरकार ने राज्य के किसानों को राहत देते हुए जायद (ग्रीष्मकालीन) मूंग की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया है। राज्य में जायद मूंग की खरीद 7 जुलाई से शुरू होगी। यह खरीद केंद्र सरकार की पीएम-आशा योजना के तहत प्राइस सपोर्ट स्कीम के जरिए की जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि बाजार में मूंग का भाव एमएसपी से नीचे जाने पर किसानों को नुकसान से बचाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री जीतूभाई वाघाणी ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना और बाजार में कीमत गिरने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देना है।

जायद मूंग के लिए कितना एमएसपी तय?

केंद्र सरकार ने इस साल जायद मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,768 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। अगर बाजार में भाव इससे कम हो जाए तो सरकार एमएसपी पर मूंग खरीद लेगी, ताकि किसानों को नुकसान न हो। सरकार ने बताया कि प्रत्येक किसान से खरीदी जाने वाली मूंग की मात्रा उसकी बोई गई जमीन के आधार पर तय होगी। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 1,200 किलोग्राम उत्पादन का मानक रखा गया है। वहीं, एक किसान से अधिकतम 1,500 किलोग्राम यानी 75 मन मूंग ही खरीदी जा सकेगी।

अमेरिका के होटल में लगी आग, जान बचाने के लिए खुद को बाथरूम में किया लॉक: गुजराती परिवार की दम घुटने से मौत

खेड़ा। अमेरिका के मैसाचुसेट्स के वॉर्सेस्टर शहर से बुरी खबर सामने आई है। यहां नाडियाड के रहने वाले एक गुजराती परिवार के तीन सदस्यों की होटल में आग लगने से मौत हो गई। परिवार इकोनो लॉज में ठहरा था। घटना की सूचना मिलते ही नाडियाड में शोक की लहर दौड़ गई।

होटल में आग से गुजराती परिवार की मौत

मृतकों की पहचान हितेश सुथार, हिनाबेन और ईशानी के रूप में हुई है। जो मूल रूप से नाडियाड के रहने वाले थे। सुथार अपनी पत्नी हिनाबेन और 20 साल की बेटे ईशानी के साथ पिछले दो सालों से अमेरिका में रह रहे थे। सुथार परिवार ने विदेश में एक अच्छे भविष्य का सपना देखा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक छोटी सी गलती और एक इस आपदा ने इस पूरे परिवार को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया।

बाथरूम में खुद को किया लॉक

वॉर्सेस्टर के इकोनो लॉज में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते धुंआ और आग पूरे होटल के कमरे में फैल गया। आग के फैलते ही घबराए परिवार ने खुद को बचाने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए, परिवार के तीनों सदस्य बाथरूम में गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। हालांकि, यह फैसला उनके लिए घातक साबित हुआ। होटल में आग पर काबू पाने में काफी समय लगा, जिसके चलते बाथरूम में मौजूद परिवार के सदस्य अंदर फैले धुएं में दम घुटने से मर गए।

आग के कारणों की हो रही जांच

इस घटना की खबर फैलते ही नाडियाड में उनके परिवार और दोस्तों में शोक की लहर दौड़ गई। उनके परिजनों के लिए यह बात सोच पाना मुश्किल हो रहा है कि विदेश में बसे एक परिवार को ऐसी मौत का सामना करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन आग लगने के सटीक कारण की जांच कर रहा है।

गुजरात में बारिश बनी आफत: जूनागढ़ में गड्ढे में गिरे बाइक सवार का सिर फटा, वेरावल में खुले सीवर में बहे पिता और दो बच्चे

जूनागढ़ में गड्ढे में गिरे बाइक सवार दंपत्ति, गंभीर चोट

वेरावल में खुले सीवर में गिरे पिता-बच्चे, बाल-बाल बचे

बारिश ने खोली नगर निगमों की मॉनसून-पूर्व तैयारियों की पोल

अहमदाबाद। जूनागढ़ जिले में बारिश के पहले दौर में ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मॉनसून-पूर्व तैयारी की पोल खुल गई है। लगातार बारिश से शहर में जगह-जगह पानी भरने के साथ-साथ सड़कों पर बने गड्ढे भी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। खासकर शहर के आजाद चौक और ओघड़नगर इलाकों में प्रशासन की लापरवाही के कारण कई हादसे हुए हैं।

औंधे मुंह गिरे बाइक सवार दंपत्ति

जूनागढ़ शहर के आजाद चौक इलाके में सड़क की खुदाई के बाद ठीक से मरम्मत न होने की वजह से एक बड़ा गड्ढा बन गया था। बारिश के पानी के कारण गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे वहां से गुजर रहा एक बाइक सवार दंपत्ति अचानक गड्ढे में गिर गया। यह भयानक हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बाइक सवार के सिर में गंभीर चोट आई है और वह लंगड़ाकर चल रहा है। इस दौरान पीछे बैठी उसकी पत्नी उसे संभाले हुए है। इसके बाद आसपास के लोगों की मदद से उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

कहां का है मामला?

सिर्फ आजाद चौक ही नहीं, बल्कि ओघड़नगर इलाके में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। वहां कल, 1 जुलाई को एक घटना सामने आई जिसमें 3-4 लोग अपनी गाड़ी समेत और पैदल चलते हुए एक ही गड्ढे में गिर गए। राहत की बात बस इतनी है कि इन लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन इस घटना ने सिस्टम की पोल खोल दी है। शहर में सीवर और सड़कों के अधूरे और खराब काम को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। ये घटनाएं साबित कर रही हैं कि मॉनसून-पूर्व काम सिर्फ कागजों पर ही हुआ है। अब सवाल यह है कि यह प्रशासनिक सिस्टम कुंभकर्ण की नींद से कब जागेगा? क्या सिस्टम किसी बड़े हादसे या किसी बेगुनाह नागरिक की मौत का इंतजार कर रहा है?

वेरावल में खुले सीवर में बहे पिता और दो बच्चे

गिर सोमनाथ जिले में सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है। जिले के ज्यादातर इलाकों में चार इंच तक बारिश हुई है, जिससे सोमनाथ के हेडक्वार्टर वेरावल के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। पहली बारिश ने ही नगरपालिका के प्री-मानसून कामों की पोल खोल दी है। बारिश के इस मौसम में प्रभास पाटन के वार्ड नंबर 2 से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पिता अपनी साइकिल पर दो मासूम बच्चों के साथ बारिश के पानी से भरी सड़क से गुजर रहा था। सड़क पर खुले नाले की वजह से पिता और दोनों बच्चे अचानक नाले में गिर गए।

गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत में 100 घर ध्वस्त किए जाने पर उठाए सवाल, पहले सूचना दिए बगैर की गई कार्रवाई

अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से सूरत के नारिसनगर इलाके में 30 मई को की गई पूरी तरह गैर-कानूनी तोड़फोड़ की कार्रवाई पर उसका जवाब मांगा। पूर्व सूचना के बगैर की गई इस कार्रवाई में लगभग 100 घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से पूछा कि क्या वह अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदार नहीं है और कहा कि इस मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। सूरत नगर निगम द्वारा घर ध्वस्त किए गए जाने से प्रभावित कुछ लोगों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस निखिल करियल ने सरकार से पूछा कि पूरी तरह गैर-कानूनी तोड़फोड़ की कार्रवाई पर उसका क्या रुख है। जस्टिस करियल ने पुलिस आयुक्त से यह मौखिक सवाल भी पूछा कि घटनास्थल पर डीएसपी स्तर के अधिकारी की मौजूदगी के बावजूद इस मामले में कोई शिकायत क्यों नहीं की गई और न ही कोई जांच हुई। उन्होंने कहा, छोटी-मोटी झड़पों पर तो राज्य सरकार को चिंता होती है, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हो रही है तो उसे कोई चिंता नहीं है। राज्य सरकार को निश्चित रूप से यह पता लगाने में रुचि लेनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रदीप कुमार सोलंकी द्वारा महानगर मल्टीमीडिया प्रा. लि. जी-848, फेज 3, रीको सीतापुरा, जयपुर (राज.) से मुद्रित एवं 227-हीरालाल की गली, झालाना, मालवीय नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित।
सम्पादकः प्रदीप कुमार सोलंकी, मो. 93510-01100, Email: atulyasansar@gmail.com संपादकीय कार्यालयः जगतपुरा फ्लाईओवर के पास, जगतपुरा जयपुर।